

भारत में शहरीकरण की बढ़ती चुनौतियाँ

DR P M SHARMILA

Assistant Professor

Government first grade college Vijaynagar

Bangalore Karnataka -104

शहरीकरण या नगरीकरण आर्थिक उन्नति की सबसे बड़ी विशेषता है। शहरी क्षेत्रों के भौतिक विस्तार (क्षेत्रफल, जनसंख्या आदि का विस्तार) शहरीकरण (Urbanisation) कहलाता है। यह एक वैश्विक परिवर्तन है। संयुक्त राष्ट्र संघ की परिभाषा के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का शहरों में जाकर रहना और काम करना भी 'शहरीकरण' है। शहरीकरण या नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक समाज के समुदाय के आकार और शक्ति में वृद्धि होती रहती है जब तक की वे संपूर्ण जनसंख्या के अधिकांश भाग को सम्मिलित नहीं कर लेते हैं और सम्पूर्ण समाज पर प्रकार्यात्मक और सांस्कृतिक आधिपत्य स्थापित नहीं कर लेते। किसी राष्ट्र की जनसंख्या का बढ़ता हुआ आकार जब शहर की तरफ निवास के लिए जमा होता है तो उसे नगरीकरण या 'शहरीकरण' कहते हैं। ज्यादातर काम के अवसरों और वैसा प्रक्रिया जिसके अंतर्गत शहरों का अधिक पैमाने पर विस्तार होता है, शहरीकरण कहलाता है। उपरोक्त आधार पर यह स्पष्ट है कि शहरीकरण वास्तव में एक सतत परिवर्तनशील प्रक्रिया है, जो ग्रामीण और शहरी जीवन के बीच एक प्रकार का अंतर पैदा करती है। जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या का शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन को भी समझा जा सकता है। शहरीकरण या नगरीकरण स्वयं के विकास करने का मानक माना जाता है। जब भारी संख्या में लोग गाँवों को छोड़कर शहरों की तरफ रुख करने लगते हैं, उसे ही शहरीकरण की उपमा दी गयी है। शहरीकरण का सबसे बड़ा साथी विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टि से उन्नत भौतिक आराम की सुख-सुविधाएं हैं। जिसे देखकर अनायास ही व्यक्ति खींचा चला जाता है। और उसे पाने की चाहत में प्रयास करने लगता है। शहरीकरण से तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में आबादी की आवाजाही से है। यह मूल रूप से शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के अनुपात में क्रमिक वृद्धि है। शहरीकरण समकालीन दुनिया में काफी लोकप्रिय प्रवृत्ति है। इसके अलावा, लोग बेहतर जीवन स्तर के कारण शहरीकरण में इजाफा करते हैं। विशेषज्ञ की भविष्यवाणी के अनुसार, 2050 तक विकासशील दुनिया का लगभग 64% और विकसित दुनिया का 86% हिस्सा शहरीकृत होगा।

मूलशब्द: जनसंख्या, शहरीकरण, भारत, ग्रामीण, आर्थिक क्षेत्रों

परिचय

अर्थव्यवस्था की क्रमिक विकास के साथ, शहरीकरण की प्रक्रिया कुछ औद्योगिक शहरी केंद्रों की वृद्धि के साथ-साथ ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में अधिशेष आबादी के पलायन पर निर्भर करती है। उच्च शिक्षा और उच्च स्तरीय सम्पन्न जीवनस्तर अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को आकर्षित करता है। भारत में, शहरीकरण की ओर बढ़ते रुझान को इस वर्तमान शताब्दी की शुरुआत से ही देखा गया है। ग्रामीण-शहरी संरचना पर जनगणना के आंकड़ों से भारत में शहरीकरण की दर में लगातार वृद्धि होती आयी है और विशेष रूप से वर्तमान 21 वीं सदी के उत्तरार्ध के दौरान। शहरीकरण से तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में आबादी की आवाजाही से है। यह मूल रूप से शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के अनुपात में क्रमिक वृद्धि है। शहरीकरण समकालीन दुनिया में काफी लोकप्रिय प्रवृत्ति है। इसके अलावा, लोग ज्यादातर काम के अवसरों और बेहतर जीवन स्तर के कारण शहरीकरण में इजाफा करते हैं। विशेषज्ञ की भविष्यवाणी के अनुसार, 2050 तक विकासशील दुनिया का लगभग 64% और विकसित दुनिया का 86% हिस्सा शहरीकृत होगा। ज्यादातर काम के अवसरों और वैसा प्रक्रिया जिसके अंतर्गत शहरों का अधिक पैमाने पर विस्तार होता है, शहरीकरण कहलाता है। उपरोक्त आधार पर यह स्पष्ट है कि शहरीकरण वास्तव में एक सतत परिवर्तनशील प्रक्रिया है, जो ग्रामीण और शहरी जीवन के बीच एक प्रकार का अंतर पैदा करती है। जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या का शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन को भी समझा जा सकता है। शहरीकरण या नगरीकरण स्वयं के विकास करने का मानक माना जाता है। जब भारी संख्या में लोग गाँवों को छोड़कर शहरों की तरफ रुख करने लगते हैं, उसे ही शहरीकरण की उपमा दी गयी है। शहरीकरण का सबसे बड़ा साथी विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टि से उन्नत भौतिक आराम की सुख-सुविधाएं हैं। जिसे देखकर अनायास ही व्यक्ति खींचा चला जाता है। और उसे पाने की चाहत में प्रयास करने लगता है। शहरीकरण से तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों से

शहरी क्षेत्रों में आबादी की आवाजाही से है। यह मूल रूप से शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के अनुपात में क्रमिक वृद्धि है। शहरीकरण समकालीन दुनिया में काफी लोकप्रिय प्रवृत्ति है। इसके अलावा, लोग बेहतर जीवन स्तर के कारण शहरीकरण में इजाफा करते हैं। विशेषज्ञ की भविष्यवाणी के अनुसार, 2050 तक विकासशील दुनिया का लगभग 64% और विकसित दुनिया का 86% हिस्सा शहरीकृत होगा।

भारत, एक प्राचीन सभ्यता और गतिशील सामाजिक-सांस्कृतिक बदलावों का केंद्र, शहरीकरण के जरिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजर रहा है। भारत में शहरीकरण, जो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर व्यापक प्रवास द्वारा चिह्नित है, अवसरों और चुनौतियों का एक दिलचस्प मिश्रण लेकर आता है। भारत में, शहरी आबादी 461 मिलियन है, जो 2.3 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर का अनुभव कर रही है। अनुमान बताते हैं कि 2031 तक देश की राष्ट्रीय आय का 75 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों से उत्पन्न होगा। हालांकि, आवश्यक शहरी बुनियादी ढांचे को विकसित करने में एक बड़ी चुनौती है, वर्ष 2050 के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का 70 से 80 प्रतिशत अभी भी निर्माण का इंतजार कर रहा है। इस कमी को पूरा करने के लिए अनुमानित निवेश अंतर लगभग 827 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। तमिलनाडु भारत का सबसे अधिक शहरीकृत राज्य है, इसके बाद केरल और महाराष्ट्र का स्थान है। हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है।

भारत में शहरीकरण की पेचीदगियों को समझने से पहले, यह समझना जरूरी है कि शहरीकरण क्या है। शहरीकरण से तात्पर्य देश की आबादी के ग्रामीण इलाकों के बजाय शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों की बढ़ती हिस्सेदारी से है। यह आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारकों के कारण शहरों के विकास की विशेषता है, जो अंततः उनके विस्तार और नए शहरों के विकास की ओर ले जाता है।

भारत में शहरीकरण के कारण

भारत में शहरीकरण कई सामाजिक-आर्थिक कारकों का परिणाम है। इन कारणों को समझने से हमें भारत के ग्रामीण परिदृश्यों के शहरी केंद्रों में तब्दील होने के रूप को समझने में मदद मिलती है।

आर्थिक उत्प्रेरक

शहरीकरण को बढ़ावा देने वाले प्रमुख आर्थिक कारकों में शामिल हैं:

औद्योगीकरण: शहरी क्षेत्रों में उद्योगों की वृद्धि रोजगार के अवसर प्रदान करती है, ग्रामीण निवासियों को आकर्षित करती है और इस प्रकार शहरीकरण को बढ़ावा देती है।

सेवा क्षेत्र का विस्तार: महानगरीय शहरों में सेवा क्षेत्र, विशेषकर आईटी और आईटीईएस में तीव्र वृद्धि, शहरी प्रवास को बढ़ावा देती है।

सामाजिक कारक

शहरीकरण की प्रक्रिया में सामाजिक तत्व पूरक भूमिका निभाते हैं:

उन्नत जीवन स्तर: शहरी क्षेत्रों में बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और समग्र रूप से बेहतर जीवन स्थितियों का आकर्षण ग्रामीण निवासियों को आकर्षित करता है।

सामाजिक गतिशीलता: शहरी परिवेश द्वारा प्रदत्त ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता के अवसर कई लोगों के लिए आकर्षक संभावना हैं।

जनसांख्यिकीय कारकों

जनसंख्या वृद्धि और प्रवास जैसे जनसांख्यिकीय पहलू शहरीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं:

जनसंख्या वृद्धि: शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि शहरीकरण को बढ़ावा देती है।

प्रवासन: ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और गरीबी जैसे कारकों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवासन, शहरीकरण की आग को भड़काता है।

शहरीकरण का महत्व

शहरीकरण किसी देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह औद्योगिकीकरण और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास के लिए उत्प्रेरक का काम करता है। इसके अतिरिक्त, शहरीकरण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं जैसे सामाजिक बुनियादी ढांचे के विकास में सहायता करता है। यह सांस्कृतिक एकीकरण को भी बढ़ावा देता है, जिससे सामाजिक उन्नति होती है।

भारत में शहरीकरण की समस्याएं

यद्यपि शहरीकरण विकास का एक शक्तिशाली चालक है, लेकिन यह कुछ चुनौतियां भी प्रस्तुत करता है जिनका तत्काल समाधान किया जाना आवश्यक है:

आवास एवं मलिन बस्ती विकास

तीव्र और अक्सर अनियमित शहरी विस्तार के परिणामस्वरूप आवास अपर्याप्त हो जाते हैं, जिससे झुग्गी-झोपड़ियाँ बढ़ती जाती हैं। बुनियादी ढांचे की कमियां

शहरी इलाकों में अक्सर अपर्याप्त बुनियादी सुविधाओं की समस्या रहती है, जिनमें जलापूर्ति, सीवेज प्रणाली, बिजली और सार्वजनिक परिवहन शामिल हैं।

संबंधी मान भंग वातावरण

त्वरित शहरीकरण से वायु और जल प्रदूषण जैसी पर्यावरणीय चिंताएं बढ़ सकती हैं, साथ ही हरित क्षेत्रों का विनाश भी हो सकता है।

सामाजिक मुद्दे

शहरीकरण से बेरोजगारी, गरीबी, यातायात भीड़ और अपराध जैसे सामाजिक मुद्दे उत्पन्न होते हैं।

भारत में शहरीकरण के प्रभाव

शहरीकरण भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है:

आर्थिक प्रभाव

सकारात्मक: शहरीकरण से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है, रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं और आय का स्तर बढ़ सकता है।

नकारात्मक: इससे क्षेत्रीय असमानताएं पैदा हो सकती हैं, जिससे धन शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हो जाएगा, जबकि ग्रामीण क्षेत्र पीछे रह जाएंगे।

सामाजिक प्रभाव

सकारात्मक: शहरीकरण के परिणामस्वरूप शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और मनोरंजन जैसी सामाजिक सेवाओं में सुधार हो सकता है।

नकारात्मक: इससे सामाजिक असमानताएं बढ़ सकती हैं और कमजोर समुदायों को हाशिए पर धकेला जा सकता है।

पर्यावरणीय प्रभाव

नकारात्मक: वनों की कटाई, प्रदूषण और अपशिष्ट प्रबंधन चुनौतियों जैसे कारकों के कारण शहरीकरण पर्यावरणीय गिरावट का कारण बन सकता है।

भारत में शहरीकरण के लिए सरकारी योजनाएँ

भारत सरकार ने चुनौतियों से निपटने और शहरीकरण की क्षमता का दोहन करने के लिए विभिन्न योजनाएँ शुरू की हैं। इनमें शामिल हैं:

स्मार्ट सिटी मिशन : इसका उद्देश्य ऐसे शहरों को बढ़ावा देना है जो मूलभूत बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं, अपने नागरिकों को सभ्य जीवन स्तर प्रदान करते हैं और 'स्मार्ट' समाधान लागू करते हैं।

कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत) : इसका उद्देश्य घरों में बुनियादी सेवाएँ (जैसे, जलापूर्ति, सीवरेज) उपलब्ध कराना और शहरों में सुविधाएँ उपलब्ध कराना है, ताकि सभी लोगों, विशेषकर गरीबों और वंचितों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) : इसका उद्देश्य शहरी गरीबों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है।

शहरीकरण के लाभ

सबसे पहले, शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में संसाधन प्रदान करने में बहुत अधिक कुशल हैं। शहरी क्षेत्रों में आवास, स्वच्छ पानी और बिजली जैसी महत्वपूर्ण और बुनियादी सुविधाएँ आसानी से उपलब्ध होते हैं।

शहरी क्षेत्रों में लोगों को विभिन्न महत्वपूर्ण सेवाओं तक पहुंचना काफी आसान लगता है। सबसे उल्लेखनीय, ये सेवाएँ उच्च-गुणवत्ता वाली शिक्षा, विशेषज्ञ स्वास्थ्य देखभाल, सुविधाजनक परिवहन, मनोरंजन आदि हैं। इसके अलावा, कुछ या सभी सेवाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में अनुपलब्ध हैं।

शहरी क्षेत्र बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। ये रोजगार के अवसर औद्योगीकरण और व्यवसायीकरण के परिणामस्वरूप हैं।

शहरी क्षेत्र ज्ञान के निर्माता और प्रसारकर्ता के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसकी वजह है, अत्यधिक जुड़ी शहरी दुनिया। सबसे उल्लेखनीय, शहरी क्षेत्रों में लोगों की भौगोलिक निकटता विचारों के प्रसार में मदद करती है।

शहरी क्षेत्र तकनीकी विकास के लाभों का आनंद लेते हैं। शहरी क्षेत्रों में कई प्रकार की प्रौद्योगिकियाँ लागू होती हैं। इसके अलावा, शहरी लोग नवीनतम तकनीक के संपर्क में जल्दी आते हैं। इसके विपरीत, कई ग्रामीण व्यक्ति कई प्रकार की तकनीकों से अनभिज्ञ रहते हैं।

शहरीकरण के कारण

सबसे पहले, राजनीतिक कारण शहरीकरण में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक अशांति के कारण कई लोग शहरी क्षेत्रों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसलिए, कई परिवार भोजन, आश्रय और रोजगार की तलाश में शहरी क्षेत्रों में जाते हैं।

शहरीकरण का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण आर्थिक कारण है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एक व्यापक घटना है। किसानों को पर्याप्त पैसा कमाने और जीवन यापन करने में बहुत मुश्किल होती है। नतीजतन, ग्रामीण लोग बेहतर रोजगार के अवसरों की तलाश में शहरी क्षेत्रों का रुख करते हैं।

शिक्षा शहरीकरण का एक मजबूत कारण है। शहरी क्षेत्र उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करते हैं। इसके अलावा, शहरीकरण विश्वविद्यालयों और तकनीकी कॉलेजों में अध्ययन के लिए अवसर प्रदान करता है। इस तरह की उन्नत शिक्षा के अवसर ग्रामीण क्षेत्रों में कई युवा लोगों को शहरी क्षेत्रों में जाने के लिए आकर्षित करते हैं।

पर्यावरणीय गिरावट भी शहरीकरण में योगदान करने में एक भूमिका निभाती है। वनों की कटाई कई किसान परिवारों के प्राकृतिक आवास को नष्ट कर देती है। इसके अलावा, खनन और औद्योगिक विस्तार भी किसान परिवारों के प्राकृतिक आवास को नुकसान पहुंचाते हैं।

सामाजिक कारण शहरीकरण का एक और उल्लेखनीय कारण है। कई युवा ग्रामीण लोग बेहतर जीवन शैली की तलाश में शहरी क्षेत्रों में पलायन करते हैं। इसके अलावा, कई युवा ग्रामीण क्षेत्रों की रूढ़िवादी संस्कृति से बचना चाहते हैं। अधिकांश शहरी क्षेत्र अधिक आसान उदारवादी जीवन शैली प्रदान करते हैं। अधिकांशतः शहरों में युवाओं को आकर्षित करने के लिए बहुत सी चीजें होती हैं।

तीव्र शहरीकरण के परिणाम:

तेजी से बढ़ता शहरीकरण स्वस्थ और अस्वास्थ्यकर परिणाम और पहलु दोनों के अधीन है।

(i) स्वस्थ पहलू:

तेजी से फैलते औद्योगीकरण से कई औद्योगिक शहरों का स्थापना और विकास हुआ है। विनिर्माण इकाइयों के साथ, उन शहरी क्षेत्रों में सहायक और सेवा क्षेत्र बढ़ने लगे।

दूसरे, नए और अतिरिक्त रोजगार के अवसर शहरी क्षेत्रों में अपनी नई विस्तार विनिर्माण और सेवा क्षेत्र इकाइयों में बनाए जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण-शहरी प्रवास और “औद्योगिकीकरण-शहरीकरण प्रक्रिया” स्थापित की जाती है।

तीसरा, शहरों का विकास बाहरी अर्थव्यवस्थाओं को जन्म दे सकता है ताकि विभिन्न सेवाओं और गतिविधियों के लिए अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठा सके।

अंत में, शहरीकरण के परिणामों में परिवर्तन होता है और शहरी लोगों की मानसिकता में व्यवहार और उचित प्रेरणा में आधुनिकीकरण होता है जो अप्रत्यक्ष रूप से देश को तेजी से आर्थिक विकास प्राप्त करने में मदद करता है।

(ii) अस्वस्थ पहलू:

हालाँकि अर्थव्यवस्था का विकास शहरीकरण से बहुत जुड़ा हुआ है, लेकिन इससे कुछ गंभीर समस्याएं पैदा हुई हैं। सबसे पहले, बढ़ते शहरीकरण शहरी क्षेत्रों में बढ़ती भीड़ के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। बहुत अधिक भीड़ के कारण ट्रेफिक जाम, आबादी की बहुत अधिक जमावट जैसी समस्याएं हुई हैं, जिसका प्रबंधन धीरे-धीरे बहुत मुश्किल और महंगा होता जा रहा है।

दूसरे, बहुत अधिक जनसंख्या शहरीकरण का एक और अस्वास्थ्यकर पहलू है जो शहरी आवास, शिक्षा, चिकित्सा सुविधाओं, मलिन बस्तियों के विकास, बेरोजगारी, हिंसा, भीड़भाड़ आदि से संबंधित शहरी अराजकता पैदा करता है। इन सभी के परिणामस्वरूप मानव जीवन की गुणवत्ता में गिरावट होती है।

(iii) शहरी नीति के उपाय:

तीव्र शहरीकरण के अस्वास्थ्यकर परिणामों को ध्यान में रखते हुए, एक शहरी नीति तैयार करना काफी महत्वपूर्ण है जो न्यूनतम अवांछनीय प्रभावों के साथ शहरी विकास प्रदान कर सकता है।

जिन उपायों का बड़े पैमाने पर पालन किया जा सकता है, उनमें शामिल हैं :

(i) गैर-कृषि गतिविधियों के विकास के लिए देश की विकास योजनाओं के साथ शहरीकरण प्रक्रिया को एकीकृत करना, जैसे कि बाहरी अर्थव्यवस्थाओं की प्राप्ति के लिए विनिर्माण सेवाएं और बुनियादी ढाँचा।

(ii) इन बड़े आकार के शहरों के नुकसान को कम करने के लिए चयनात्मक शहरी विकास की व्यवस्था करना,

(iii) ग्रामीण जिलों को विकसित करने के लिए, अत्यधिक ग्रामीण जिलों के शहरों को विकसित करके, बड़े शहरों में और उसके आसपास उपग्रह टाउनशिप विकसित करना।

(iv) नगरीय सुविधाओं को पर्याप्त मात्रा में विकसित करके बड़े शहरी केंद्रों पर दबाव बढ़ाना ताकि शहरी जीवन को शांतिपूर्ण बनाया जा सके।

भारत, एक प्राचीन सभ्यता और गतिशील सामाजिक-सांस्कृतिक बदलावों का केंद्र, शहरीकरण के जरिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजर रहा है। भारत में शहरीकरण, जो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर व्यापक प्रवास द्वारा चिह्नित है, अवसरों और चुनौतियों का एक दिलचस्प मिश्रण लेकर आता है। भारत में, शहरी आबादी 461 मिलियन है, जो 2.3 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर का अनुभव कर रही है। अनुमान बताते हैं कि 2031 तक देश की राष्ट्रीय आय का 75 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों से उत्पन्न होगा। हालांकि, आवश्यक शहरी बुनियादी ढांचे को विकसित करने में एक बड़ी चुनौती है, वर्ष 2050 के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का 70 से 80 प्रतिशत अभी भी निर्माण का इंतजार कर रहा है। इस कमी को पूरा करने के लिए अनुमानित निवेश अंतर लगभग 827 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2035 तक भारत की शहरी आबादी 675 मिलियन तक पहुँचने का अनुमान है, जो चीन की एक बिलियन आबादी के बाद दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी आबादी होगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि कोविड-19 महामारी के प्रभाव के बावजूद, वैश्विक शहरी आबादी अपनी वृद्धि की गति को फिर से शुरू कर रही है और वर्ष 2050 तक इसमें 2.2 बिलियन की वृद्धि होने की उम्मीद है। 2021 में भारत में शहरीकरण दर 1.34% बताई गई है। भारत, एक प्राचीन सभ्यता और गतिशील सामाजिक-सांस्कृतिक बदलावों का केंद्र, शहरीकरण के जरिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजर रहा है। भारत में शहरीकरण, जो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर व्यापक प्रवास द्वारा चिह्नित है, अवसरों और चुनौतियों का एक दिलचस्प मिश्रण लेकर आता है। भारत में, शहरी आबादी 461 मिलियन है, जो 2.3 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर का अनुभव कर रही है। अनुमान बताते हैं कि 2031 तक देश की राष्ट्रीय आय का 75 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों से उत्पन्न होगा। हालांकि, आवश्यक शहरी बुनियादी ढांचे को विकसित करने में एक बड़ी चुनौती है, वर्ष 2050 के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का 70 से 80 प्रतिशत अभी भी निर्माण का इंतजार कर रहा है। इस कमी को पूरा करने के लिए अनुमानित निवेश अंतर लगभग 827 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। तमिलनाडु भारत का सबसे अधिक शहरीकृत राज्य है, इसके बाद केरल और महाराष्ट्र का स्थान है। हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है। भारत में शहरीकरण की पेचीदगियों को समझने से पहले, यह समझना जरूरी है कि शहरीकरण क्या है। शहरीकरण से तात्पर्य देश की आबादी के ग्रामीण इलाकों के बजाय शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों की बढ़ती हिस्सेदारी से है। यह आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारकों के कारण शहरों के विकास की विशेषता है, जो अंततः उनके विस्तार और नए शहरों के विकास की ओर ले जाता है।

भारत तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है। 2011 के 31% प्रतिशत की तुलना में, 2036 तक भारत के शहर और कस्बे 60 करोड़ लोगों या 40% आबादी के लिए रहने लायक होंगे और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में शहरी क्षेत्रों का लगभग 70% योगदान होगा। भारत इस शहरी बदलाव का कितनी अच्छी तरह से प्रबंधन करता है, यह 2047 तक, यानी आजादी के 100 साल पूरे होने पर विकसित देश बनने की उसकी महत्वाकांक्षा को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। निजी वित्तीय सहायता को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। ऐसे में जबकि 160 से अधिक भारतीय शहरों को निवेश ग्रेड के रूप में वर्गीकृत (क्लासीफाइड) किया गया है, सरकारी फंडिंग पर निर्भरता अधिक बनी हुई है। केंद्र और राज्य सरकारें शहरी बुनियादी ढांचे का 72% धन उपलब्ध कराती हैं, जबकि व्यवसायों से केवल 5% धन प्राप्त होता है। इन चुनौतियों को पहचानते हुए, सरकार ने व्यवसायों से धन प्राप्त करने

के लिए उपाय किए हैं, लेकिन आर्थिक रूप से मजबूत शहरों में भी इसका उपयोग बेहद सीमित है। निजी पूंजी का लाभ उठाने के लिए, शहरी स्थानीय निकायों (अ को व्यापक रूप से अपनी क्षमता का निर्माण करने और बैंक सक्षम परियोजनाओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। देश के लिए नगर पालिका बांड बाजार को विकसित करना और वित्त जुटाने के नवीन साधन प्रस्तुत करना भी महत्वपूर्ण होगा। भारत एक जल संकटग्रस्त देश है, जल सुरक्षा के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा तैयार करना उतना ही आवश्यक है। उदाहरण के लिए, सूरत बड़े पैमाने पर अपशिष्ट जल का रिसाइक्लिंग करने वाले पहले शहरों में से एक बन गया है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर धारमपुरी ने जल आपूर्ति के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करके, हर घर को सीवरेज सिस्टम से जोड़कर और अपशिष्ट जल को रिसाइकिल करके पानी के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है।

उपसंहार

परिणामस्वरूप, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारत में प्रतिदिन शहरीकरण बढ़ रहा है, जिसमें संभावनाओं और उच्च जीवन स्तर के लिए पूर्ण समर्थन है। हालाँकि, जैसे-जैसे शहरीकरण तेज़ होता है, यह संतुलित, निष्पक्ष और समावेशी विकास में बाधाएँ पैदा करता है। लोग एक-दूसरे की संस्कृतियों के बारे में सीखते हैं और ज्ञान साझा करते हैं, जो लोगों के बीच की सीमाओं को तोड़ने में मदद करता है। वास्तव में, सामाजिक संरचनाएँ बिखर रही हैं, जैसे कि पारिवारिक संरचनाएँ संयुक्त से एकल में परिवर्तित हो रही हैं। अंत में, शहरीकरण के परिणामों में परिवर्तन होता है और शहरी लोगों की मानसिकता में व्यवहार और उचित प्रेरणा में आधुनिकीकरण होता है जो अप्रत्यक्ष रूप से देश को तेजी से आर्थिक विकास प्राप्त करने में मदद करता है। शहरीकरण एक प्रक्रिया है जो निरंतर वृद्धि पर है। इसके अलावा, शहरीकरण ग्रामीण संस्कृति को शहरी संस्कृति में बदलना सुनिश्चित करता है। इन सबके बावजूद सरकार को तेजी से बढ़ते शहरीकरण के लिए सतर्क रहना चाहिए। एक पूरी तरह से शहरीकृत दुनिया हमारी दुनिया की अंतिम नियति की तरह दिखती है। सामाजिक और आर्थिक दबावों के कारण, पिछड़े गाँवों के लोग नौकरी की तलाश में शहरीकृत केंद्रों की ओर रुख करने लगते हैं। जहाँ साथ ही नव स्थापित उद्योग और सहायक गतिविधियाँ उन लोगों को नौकरी के अवसर लगातार दे रही हैं जो शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। यदि औद्योगिक विकास तेज है तो शहरीकरण की गति तेज है। शहरीकरण की गति धीरे-धीरे कम हो जाती है, जब देश की कुल आबादी में शहरी आबादी का अनुपात बहुत अधिक हो जाता है। शहरीकरण बुरा नहीं है, किन्तु जैसे हर चीज की अति खराब होती है, वही स्थिति इसके साथ भी है। हमारा देश कृषि-प्रधान देश है, लेकिन शहरीकरण के फलस्वरूप कोई भी युवा गाँवों में रहकर खेती नहीं करना चाहता, और न ही गाँवों में रहना चाहता है। शहरों की चकाचौंध में वो खो सा गया है। उसे वास्तविकता का जरा सा भी भान नहीं है। कोई खेती नहीं करेगा, तो देश की जनता खाएगी क्या। आप शहरी हो या ग्रामीण, पेट भरने के लिए सबको भोजन की ही आवश्यकता होती है। और उसकी उगाही केवल किसान ही कर सकता है, जिसके लिए गाँव में रहना जरूरी है। शहरीकरण या नगरीकरण स्वयं के विकास करने का मानक माना जाता है। जब भारी संख्या में लोग गाँवों को छोड़कर शहरों की तरफ रुख करने लगते हैं, उसे ही शहरीकरण की उपमा दी गयी है। शहरीकरण का सबसे बड़ा साथी विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टि से उन्नत भौतिक आराम की सुख-सुविधाएँ हैं। जिसे देखकर अनायास ही व्यक्ति खींचा चला जाता है। और उसे पाने की चाहत में प्रयास करने लगता है।

संदर्भ ग्रन्थसूची

- भारत में शहरीकरण
- भूमि उपयोग
- शहरीकरण का अभिशाप
- ‘भारत में बढ़ता शहरीकरण अमेरिका के हित में’
- शहरीकरण और स्वास्थ्य स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां
- शहरीकरण का बोझ नहीं सह पाएगा धरती का पर्यावरण
- शहरीकरण के साथ सुविधाएं बढ़ाई
- नगरीय भूगोल
- शहरीकरण

